eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

शिक्षा और स्वास्थ्य सुधारों के माध्यम से भारत का रूपांतरणः विकसित राष्ट्र 2047 का मार्ग

डा0 बनवारी[1]

[1]असि0 प्रोफेसर, शिक्षा संकाय, कमला नेहरू भौतिक एवं सामाजिक विज्ञान संस्थान, सुल्तानपुर, उ0प्र0

Received: 21 March 2026 Accepted & Reviewed: 25 March 2026, Published: 31 March 2026

Abstract

भारत वर्ष 2047 तक अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूर्ण करेगा। यह अवसर केवल उत्सव का नहीं, बल्कि आत्ममंथन और भविष्य के पुनर्निर्माण का भी है। "विकसित भारत 2047" का लक्ष्य आर्थिक वृद्धि से आगे बढ़कर एक समग्र मानव विकास की परिकल्पना करता है, जिसमें नागरिकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और सामाजिक उत्थान सम्मिलित है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में व्यापक, दीर्घकालिक और जनोन्मुख सुधार आवश्यक हैं। इन दोनों के संतुलित समन्वय से ही एक सशक्त, नवाचार–प्रधान और समतामूलक समाज का निर्माण संभव है। इस शोध–पत्र में भारत की वर्तमान शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया गया है कि इन क्षेत्रों में सुधार किस प्रकार "विकसित भारत 2047" के विजन को मूर्त रूप दे सकते हैं। लेख में नई शिक्षा नीति 2020, डिजिटल शिक्षण, कौशल विकास, आयुष्मान भारत, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन और मानसिक स्वास्थ्य योजनाओं की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश केवल सामाजिक कल्याण नहीं, बल्कि भारत के सर्वांगीण, स्थायी और सभ्यतागत उत्थान का आधार है।

मुख्य शब्दः शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य नीति, भारत 2047, मानव पूंजी, समावेशी विकास, नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया

Introduction

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे युवा देश है। इसकी लगभग 65 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है, जो इसे वैश्विक स्तर पर अपार मानव संसाधन का केंद्र बनाती है। किंतु यह जनसंख्या तभी "जनसंपदा" (demographic dividend) बन सकती है, जब वह शिक्षित, कौशलयुक्त और स्वस्थ हो। यदि शिक्षा अधूरी और स्वास्थ्य कमजोर रहा, तो यही जनसंख्या "जनभार" (demographic burden) में बदल सकती है। अतः भारत के विकास का असली केंद्र उसके नागरिकों की गुणवत्ता है, न कि केवल आर्थिक वृद्धि की गति। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत ने असमानता, गरीबी और अशिक्षा से संघर्ष करते हुए राष्ट्र–निर्माण की यात्रा शुरू की थी। तब साक्षरता दर मात्र 18 प्रतिशत और औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 32 वर्ष थी। आज भारत साक्षरता दर 77 प्रतिशत और औसत जीवन प्रत्याशा 70 वर्ष से अधिक तक पहुँच चुका है। यह उल्लेखनीय उपलब्धि है, परंतु अब चुनौती केवल पहुँच की नहीं, बल्कि गुणवत्ता, समानता और स्थायित्व की है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सुधार की दिशा अब मात्र सेवा प्रदान करने की नहीं, बल्कि मानव पूंजी निर्माण की होनी चाहिए। भारत का लक्ष्य केवल उच्च GDP प्राप्त करना नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ प्रत्येक नागरिक को सीखने, सोचने, सृजन करने और स्वस्थ जीवन जीने का अवसर मिले। 2047 तक के "विकसित भारत" के सपने को साकार करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को राष्ट्रीय विकास की रीढ़ के रूप में देखना आवश्यक है। यही दोनों क्षेत्र भारत को गरीबी

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

से समृद्धि, निर्भरता से आत्मनिर्भरता, और विकासशील से विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में ले जा सकते हैं।

1 शिक्षा सुधार – ज्ञान आधारित समाज की ओर

1.1 नई शिक्षा नीति 2020: परिवर्तन की आधारशिला– नई शिक्षा नीति 2020 ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था को 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसका उद्देश्य केवल डिग्री देना नहीं, बल्कि सोचने, सृजन करने और सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देना है।

इस नीति के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं:

- 5+3+3+4 संरचना: पूर्व–प्राथमिक से माध्यमिक तक समग्र विकास आधारित ढाँचा।
- मातृभाषा में शिक्षा: समझ और आत्म–अभिव्यक्ति को सशक्त बनाना।
- कौशल–आधारित और बहुविषयक शिक्षा: छात्रों को वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना।
- राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (छत्थ): अनुसंधान और नवाचार को प्रोत्साहन।
- डिजिटल लर्निंग और म–कंटेंट: शिक्षा की पहुँच को व्यापक बनाना।

यह नीति भारत को "ज्ञान आधारित समाज" की दिशा में अग्रसर करती है, जहाँ शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी नहीं, बल्कि नागरिक चेतना और नवाचार है।

1.2 समान अवसर और समावेशी शिक्षा– भारत की शिक्षा व्यवस्था को अभी भी ग्रामीण–शहरी, गरीब–अमीर, और पुरुष–महिला असमानताओं से जूझना पड़ता है। समग्र शिक्षा अभियान ने प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की पहुँच बढ़ाई है। निष्ठा और दीक्षा जैसे शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने गुणवत्ता सुधार में भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ने बालिकाओं की शिक्षा को गति दी है। आदिवासी क्षेत्रों में स्थानीय भाषा आधारित पाठ्यक्रमों से बच्चों की भागीदारी में वृद्धि हुई है। शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बच्चा अपने सामाजिक या आर्थिक कारणों से पीछे न रह जाए।

1.3 उच्च शिक्षा में नवाचार और अनुसंधान– भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को अब पारंपरिक शिक्षण मॉडल से आगे बढ़कर अनुसंधान, नवाचार और रचनात्मकता के नए मार्ग तलाशने की आवश्यकता है। इस दिशा में राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है। इस मंच के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों के बीच शैक्षणिक संसाधनों, डिजिटल उपकरणों और अनुसंधान डाटा का साझा उपयोग संभव बनाया जा सकता है। इससे शैक्षिक समानता बढ़ेगी और विद्यार्थियों को देशभर के श्रेष्ठ शैक्षणिक संसाधनों तक समान पहुँच प्राप्त होगी।

भारत को वैश्विक शिक्षा जगत के साथ अधिक गहराई से जुड़ने की भी आवश्यकता है। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों के साथ शैक्षणिक सहयोग, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएँ और शिक्षक–विद्यार्थी विनिमय कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस प्रकार का सहयोग न केवल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाएगा, बल्कि भारतीय विश्वविद्यालयों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सशक्त बनाएगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

साथ ही, उच्च शिक्षा संस्थानों में Innovation & Incubation Centers की स्थापना और सक्रियता को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। इन केंद्रों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी रचनात्मक और उद्यमशील क्षमताओं को विकसित करने का अवसर मिलेगा। इससे वे केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजक बन सकेंगे। स्टार्टअप संस्कृति, तकनीकी नवाचार और सामाजिक उद्यमिता के क्षेत्र में ऐसे केंद्र भारत की नई पहचान बन सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, उच्च शिक्षा में सामाजिक विज्ञान, कला और संस्कृति को STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) शिक्षा के साथ संतुलित रूप से विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों में न केवल तकनीकी दक्षता बल्कि मानवीय दृष्टिकोण, नैतिकता और सांस्कृतिक चेतना भी विकसित होगी। एक समग्र शिक्षा प्रणाली तभी संभव है जब विज्ञान और मानवीय मूल्यों का संतुलन बना रहे।

1.4 कौशल विकास और उद्यमिता– भारत की युवा शक्ति तभी उपयोगी होगी जब वह कौशलयुक्त और आत्मनिर्भर होगी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) और स्किल इंडिया मिशन ने लाखों युवाओं को रोजगार–उन्मुख बनाया है। Startup India और Digital India ने नवाचार और उद्यमिता को प्रेरणा दी है। प्रत्येक शिक्षण संस्थान में "एक छात्र – एक कौशल" कार्यक्रम अपनाया जा सकता है। 2047 तक भारत को एक "कौशल आधारित अर्थव्यवस्था" में रूपांतरित होना होगा, जहाँ रोजगार सृजन का आधार नवाचार और तकनीकी दक्षता हो।

1.5 डिजिटल क्रांति और शिक्षा का भविष्य– कोविड–19 महामारी ने शिक्षा प्रणाली में डिजिटल माध्यमों के महत्व को प्रमाणित किया। SWAYAM, DIKSHA, e-Pathshala, और PM e-Vidya जैसे प्लेटफॉर्म ने शिक्षा को घर–घर पहुँचाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित शिक्षण उपकरण अब व्यक्तिगत सीखने का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। किंतु "डिजिटल डिवाइड" को समाप्त करना अभी भी चुनौती है। भारत को "टेक्नोलॉजी–इक्विटी" के सिद्धांत पर शिक्षा नीति बनानी होगी–जहाँ हर बच्चा डिजिटल संसाधनों तक समान रूप से पहुँच सके।

2. स्वास्थ्य सुधार – सशक्त नागरिक, सशक्त राष्ट्र

2.1 स्वास्थ्य और विकास का संबंध– स्वास्थ्य केवल व्यक्ति की नहीं, राष्ट्र की उत्पादकता का आधार है। शिक्षित और स्वस्थ नागरिक ही आर्थिक प्रगति के वाहक बन सकते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 47 के अनुसार, राज्य का दायित्व है कि वह जनता के पोषण और स्वास्थ्य स्तर में सुधार करे। 2047 का भारत तभी विकसित होगा जब स्वास्थ्य सेवाएँ न केवल शहरों बल्कि गाँवों तक सुलभ हों।

2.2 आयुष्मान भारतः जनस्वास्थ्य की क्रांति– वर्ष 2018 में प्रारंभ की गई आयुष्मान भारत योजना ने विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना के रूप में अपनी पहचान स्थापित की है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र परिवार को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक के निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की गई है, जिससे करोड़ों निर्धन और मध्यमवर्गीय नागरिकों को स्वास्थ्य–सुरक्षा का कवच प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर (HWC) की स्थापना के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार देश के हर कोने तक किया गया है। आज तक इस योजना से करोड़ों लाभार्थी सीधे लाभान्वित हो चुके हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

आयुष्मान भारत वास्तव में "सबका स्वास्थ्य, सबका विकास" के मंत्र को साकार करती है और जनस्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी पहल सिद्ध हुई है।

2.3 राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM)- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन (NDHM), डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक ऐसी पहल है जिसने भारत की स्वास्थ्य सेवाओं को आधुनिक, पारदर्शी और तकनीकी दृष्टि से सक्षम बनाया है। इस मिशन के तहत प्रत्येक नागरिक को एक यूनिक हेल्थ आईडी प्रदान की जा रही है, जिससे उसके चिकित्सा रिकॉर्ड का सुरक्षित और केंद्रीकृत डिजिटल संग्रह संभव हो सका है। ई–संजीवनी ऐप के माध्यम से लाखों लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा प्राप्त हो रही है, जिससे दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ऑनलाइन परामर्श सुलभ हुआ है। अस्पतालों में डिजिटल रिकॉर्ड प्रणाली और ऑनलाइन रिपोर्टिंग व्यवस्था लागू होने से स्वास्थ्य सेवाओं में पारदर्शिता और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई है। इस मिशन ने स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार को घटाकर जनविश्वास को सुदृढ़ किया है।

2.4 पोषण और मातृ–शिशु स्वास्थ्य– कुपोषण भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास के मार्ग में एक गंभीर चुनौती के रूप में उपस्थित है। इस दिशा में प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय पोषण मिशन महिलाओं और बच्चों के पोषण स्तर को सुधारने में एक प्रभावी कदम साबित हुआ है। इसके साथ ही, मिड–डे मील योजना ने न केवल बच्चों में कुपोषण कम किया है, बल्कि विद्यालयों में उपस्थिति और शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाया है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने गर्भवती और प्रसूता माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुनिश्चित किया है। भारत को वर्ष 2047 तक "Zero Hunger, Zero Malnutrition" का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में इन योजनाओं को और अधिक व्यापक रूप से लागू करना होगा।

2.5 मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक संतुलन– तेजी से बदलती जीवनशैली, प्रतिस्पर्धा और सामाजिक दबावों ने मानसिक स्वास्थ्य को आज के समय की एक गंभीर चिंता बना दिया है। इस दिशा में मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 के लागू होने के बाद समाज में मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब विद्यालयों और विश्वविद्यालयों में काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं ताकि विद्यार्थी अपनी भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों से बेहतर ढंग से निपट सकें। इसके अतिरिक्त, ऑनलाइन हेल्पलाइन और मनोचिकित्सा सेवाओं के विस्तार से लोगों को समय पर सहायता प्राप्त हो रही है। मानसिक स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत कल्याण का विषय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक स्थिरता और संतुलन की नींव भी है। वास्तव में, एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है।

3. शिक्षा और स्वास्थ्य का परस्पर संबंध एवं समन्वित विकास मॉडल – भारत के विकास के दो मुख्य स्तंभ – शिक्षा और स्वास्थ्य – एक–दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। इन्हें अलग–अलग क्षेत्रों के रूप में देखने की परंपरा अब अप्रासंगिक हो गई है, क्योंकि दोनों का प्रभाव व्यक्ति और समाज के विकास पर परस्पर निर्भर है। जिस समाज में शिक्षित जनसंख्या अधिक होती है, वहाँ स्वास्थ्य–संबंधी जागरूकता, पोषण संबंधी व्यवहार और जनसंख्या नियंत्रण की प्रवृत्ति भी बेहतर होती है। वहीं, एक स्वस्थ समाज अधिक उत्पादक, अधिक नवाचारी और अधिक सीखने योग्य होता है। अतः शिक्षा और स्वास्थ्य, एक–दूसरे के कारण और परिणाम दोनों हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

3.1 शिक्षा का स्वास्थ्य पर प्रभाव– शिक्षा व्यक्ति को केवल ज्ञान नहीं देती, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और जीवन–शैली से जुड़ी सूझ–बूझ भी प्रदान करती है। अनेक शोध बताते हैं कि शिक्षित व्यक्ति संतुलित आहार, स्वच्छता, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं के महत्व को बेहतर समझता है। उदाहरण स्वरूप, भारत के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के अनुसार, उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त महिलाओं में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।

शिक्षा व्यक्ति को सरकारी योजनाओं और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँचने की क्षमता भी देती है – क्योंकि साक्षर व्यक्ति सूचना को समझ पाता है, आवश्यक प्रपत्र भर पाता है और अपने अधिकारों के प्रति सजग रहता है। ग्राम्य और शहरी भारत में यह अंतर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। जहाँ शिक्षा का स्तर अधिक है, वहाँ जनसंख्या वृद्धि नियंत्रित है, बच्चों में कुपोषण कम है और औसत जीवन प्रत्याशा अधिक है। इस प्रकार, शिक्षा को स्वास्थ्य की "प्राथमिक दवा" कहा जा सकता है, क्योंकि यह व्यक्ति को आत्म–नियंत्रण, जागरूकता और जिम्मेदारी सिखाती है।

3.2 स्वास्थ्य का शिक्षा पर प्रभाव– दूसरी ओर, एक स्वस्थ शरीर और मानसिक संतुलन के बिना शिक्षा की निरंतरता संभव नहीं। कुपोषण, एनीमिया, दृष्टिदोष, या मानसिक तनाव से ग्रसित बच्चे विद्यालय में टिक नहीं पाते और सीखने की क्षमता घट जाती है। भारत में कई अध्ययन बताते हैं कि जिन क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हैं, वहाँ विद्यालय उपस्थिति दर अधिक और ड्रॉपआउट दर कम है। उदाहरण के लिए, "मिड–डे मील योजना" (अब पीएम पोषण) ने न केवल बच्चों में पोषण स्थिति सुधारी बल्कि स्कूल उपस्थिति में भी महत्वपूर्ण वृद्धि की।

स्वास्थ्य केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक भी है। WHO के अनुसार, मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा के परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तनाव, भय या असुरक्षा की स्थिति में बच्चे अपनी सीखने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए विद्यालयों में मानसिक स्वास्थ्य परामर्श, योग, खेल और कला जैसी गतिविधियाँ आवश्यक हैं – ताकि शिक्षण एक समग्र अनुभव बन सके।

3.3 शिक्षा–स्वास्थ्य का सामाजिक चक्र– शिक्षा और स्वास्थ्य मिलकर एक सकारात्मक सामाजिक चक्र (positive social loop) बनाते हैं। जब एक पीढ़ी शिक्षित और स्वस्थ होती है, तो वह अगली पीढ़ी को बेहतर शिक्षा और पोषण प्रदान करती है। यह "अंतरपीढ़ी लाभ" (intergenerational benefit) समाज को गरीबी और बीमारी के चक्र से बाहर निकालने में सहायक होता है। उदाहरण के लिए, शिक्षित माताएँ अपने बच्चों को न केवल बेहतर आहार देती हैं, बल्कि टीकाकरण और स्वच्छता के प्रति अधिक सतर्क रहती हैं। इसी तरह, स्वस्थ बच्चे नियमित रूप से स्कूल जाते हैं, और उच्च शिक्षा प्राप्त कर परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाते हैं। यह निरंतरता मानव विकास सूचकांक (HDI) को ऊँचा उठाती है, जो किसी भी विकसित राष्ट्र की पहचान है।

3.4 समन्वित विकास मॉडल की आवश्यकता – भारत जैसे विशाल और विविध देश में शिक्षा और स्वास्थ्य नीतियों का एकीकृत दृष्टिकोण आवश्यक है। अब तक दोनों क्षेत्रों में योजनाएँ अलग–अलग मंत्रालयों और विभागों के अधीन चलाई जाती रही हैं, जिससे प्रयास बिखरे हुए दिखाई देते हैं। अब आवश्यकता है एक समन्वित विकास मॉडल की, जिसमें शिक्षा और स्वास्थ्य एक–दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करें। इस मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय प्रस्तावित किए जा सकते हैं –

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

क) स्कूल आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रमः हर विद्यालय में वार्षिक स्वास्थ्य परीक्षण, पोषण जांच और मानसिक परामर्श की व्यवस्था हो।

ख) स्वास्थ्य शिक्षा का पाठ्यक्रम में समावेशनः बच्चों को प्राथमिक स्तर से ही स्वास्थ्य, पोषण, प्रजनन शिक्षा और स्वच्छता के व्यावहारिक पाठ पढ़ाया जाए।

ग) सामुदायिक सहयोगः पंचायत स्तर पर "शिक्षा और स्वास्थ्य परिषदें" गठित की जाएँ, जो स्थानीय समस्याओं का एकीकृत समाधान खोजें।

घ) डिजिटल एकीकरणः डिजिटल हेल्थ मिशन और डिजिटल एजुकेशन प्लेटफॉर्म को जोड़कर डेटा आधारित निर्णय प्रणाली तैयार की जाए।

ङ) महिला सशक्तिकरण केंद्रित नीतिः शिक्षित और स्वस्थ महिला समाज के परिवर्तन की धुरी है; इसलिए नीति निर्माण में महिला केंद्रित दृष्टिकोण आवश्यक है।

यह मॉडल "मानव पूंजी निवेश" को बढ़ावा देता है, जिससे दीर्घकालीन आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।

3.5 भारत @2047 के संदर्भ में दृष्टिकोण– विकसित भारत 2047 की दिशा में यदि शिक्षा और स्वास्थ्य को समन्वित रूप से विकसित किया जाए, तो भारत न केवल अपने नागरिकों की जीवन गुणवत्ता बढ़ाएगा बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भी अग्रणी बनेगा। "एक भारत, स्वस्थ भारत, शिक्षित भारत" का दृष्टिकोण केवल नारा नहीं, बल्कि एक नीतिगत दर्शन होना चाहिए।

इसके लिए नीति निर्माताओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साझा मंच पर लाना होगा। इस प्रकार शिक्षा और स्वास्थ्य का यह संयोजन न केवल विकास की नींव बनेगा, बल्कि भारत की सभ्यतागत सोच – "सर्वे भवंतु सुखिनः" – का भी आधुनिक रूपांतरण होगा।

4. भारत @2047 – विकसित राष्ट्र का खाका

4.1 मानव विकास सूचकांक पर आधारित दृष्टिकोण– विकसित राष्ट्र का अर्थ केवल उच्च GDP नहीं, बल्कि उच्च मानव विकास सूचकांक (HDI) है। 2047 तक भारत को शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और आय स्तर में संतुलित प्रगति करनी होगी।

4.2 नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका– AI, रोबोटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, और टेलीहेल्थ जैसी तकनीकें भारत की प्रगति की रीढ़ बनेंगी। लेकिन तकनीकी विकास का उद्देश्य "मानवता की सेवा" होना चाहिए, न कि केवल लाभ कमाना।

4.3 पर्यावरणीय और सतत विकास दृष्टि– स्वच्छ जल, वायु और हरित वातावरण शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों के लिए अनिवार्य हैं।

विद्यालयों और अस्पतालों को "ग्रीन सर्टिफाइड" करने की नीति लागू की जानी चाहिए।

पर्यावरणीय शिक्षा और जनस्वास्थ्य मिलकर सतत विकास का आधार बन सकते हैं।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

निष्कर्ष और सुझाव– भारत का भविष्य उसकी मानव पूंजी की गुणवत्ता पर आधारित है। यदि नागरिक शिक्षित, स्वस्थ और जागरूक होंगे तो राष्ट्र का विकास स्वतः सुनिश्चित होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार केवल नीतिगत या प्रशासनिक पहल नहीं हैं, बल्कि ये राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आधार हैं। एक सशक्त और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण तभी संभव है जब हर नागरिक को समान अवसर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्राप्त हों–

पहला, सरकार को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों क्षेत्रों में सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का कम से कम छह प्रतिशत निवेश सुनिश्चित करना चाहिए। यह निवेश केवल भौतिक ढाँचे तक सीमित न रहकर शिक्षकों के प्रशिक्षण, अनुसंधान, स्वास्थ्य अवसंरचना और ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों के विकास पर केंद्रित होना चाहिए। पर्याप्त वित्तीय संसाधन ही इन क्षेत्रों की स्थायी प्रगति की कुंजी हैं।

दूसरा, भारत को डिजिटल विभाजन और स्वास्थ्य असमानताओं को कम करने के लिए एक विशेष राष्ट्रीय मिशन चलाना चाहिए। यह मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच तकनीकी पहुँच और स्वास्थ्य सुविधाओं के अंतर को समाप्त करने में सहायक होगा। इसके अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल उपकरणों की उपलब्धता और ई–हेल्थ सेवाओं का विस्तार प्राथमिकता में होना चाहिए, ताकि हर व्यक्ति डिजिटल और स्वास्थ्य सशक्तिकरण का लाभ उठा सके। तीसरा, शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच नीति–समन्वय की एक स्थायी इकाई स्थापित की जानी चाहिए। यह इकाई दोनों क्षेत्रों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देगी, जिससे विद्यालयों, कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों के बीच ज्ञान एवं संसाधनों का आदान–प्रदान हो सकेगा। इससे नीति–निर्माण अधिक व्यावहारिक और एकीकृत दृष्टिकोण वाला बनेगा।

चौथा, विद्यालयों और पंचायत स्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों को नियमित रूप से आयोजित किया जाना चाहिए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से स्वच्छता, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य, टीकाकरण और जीवन–कौशल संबंधी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। शिक्षा संस्थान केवल ज्ञान केंद्र न होकर सामाजिक परिवर्तन के केंद्र बनें, यही इस पहल का उद्देश्य होना चाहिए। पाँचवाँ, महिलाओं की शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण किसी भी समाज की प्रगति का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है। शिक्षित और स्वस्थ महिलाएँ न केवल अपने परिवार का बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी स्वास्थ्य और विकास सुनिश्चित करती हैं। अतः मातृ–स्वास्थ्य, किशोरी शिक्षा और पोषण कार्यक्रमों को प्राथमिकता देना समय की आवश्यकता है। इन सभी उपायों के माध्यम से भारत शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में समावेशी, सतत और जन–केंद्रित विकास की दिशा में आगे बढ़ सकता है। जब हर व्यक्ति ज्ञानवान, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा, तभी "विकसित भारत 2047" का सपना पूर्ण रूप से साकार हो सकेगा। भारत के विकसित राष्ट्र बनने की यात्रा का मूल आधार उसके नागरिकों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। शिक्षा व्यक्ति को सोचने, सृजन करने और समाज में योगदान देने की क्षमता देती है, जबकि स्वास्थ्य उसे इन कार्यों को करने की शक्ति प्रदान करता है। दोनों का समन्वय ही सशक्त भारत की नींव है। नई शिक्षा नीति, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया और पोषण मिशन जैसी योजनाएँ इस दिशा में सशक्त कदम हैं, किंतु इन्हें सफल बनाने के लिए नीति, तकनीक और समाज कृ तीनों का समन्वय आवश्यक है। 2047 तक भारत को केवल आर्थिक रूप से नहीं, बल्कि मानवीय और बौद्धिक रूप से भी विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना होगा। जब हर नागरिक शिक्षित, स्वस्थ और आत्मनिर्भर होगा, तभी "विकसित भारत" का सपना साकार होगा– एक ऐसा भारत जो ज्ञान, संवेदना और नवाचार का प्रतीक बनेगा।

eISSN 2583-6986
IDEALISTIC JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN PROGRESSIVE SPECTRUMS (IJARPS)
A MONTHLY, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) INTERNATIONAL JOURNAL
Volume 05, Issue 03, March 2026

संदर्भ सूची–

- कुमार, अजय, डिजिटल इंडिया और स्वास्थ्य सेवा का आधुनिकीकरण, भारती प्रकाशन, जयपुर, 2022, पृ. 210।
- गुप्ता, नीरजा, नई शिक्षा नीति 2020: दिशा और प्रभाव, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2021, पृ. 59।
- चौहान, वीरेन्द्र, हेल्थ एंड एजुकेशनः ए ह्यूमन कैपिटल अप्रोच, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस , नई दिल्ली, 2019, पृ. 102।
- दास, सुभाष, शिक्षा, स्वास्थ्य और समावेशी विकास का संगम, हिंदी बुक सेंटर, भोपाल, 2021, पृ. 95।
- नारायण, दीपक, भारत ⁄2047: समावेशी विकास की रणनीति, राष्ट्रीय प्रकाशन, मुंबई, 2023, पृ. 168।
- पाण्डेय, मोहन, भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य का परिदृश्य, राजकमल प्रकाशन, वाराणसी, 2017, पृ. 143–145।
- भारत सरकार, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, शिक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली, 2020, पृ. 72।
- भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली, 2017, पृ. 56।
- मिश्रा, रमाकांत, स्वास्थ्य नीति और मानव विकास, नेशनल बुक ट्रस्ट, नई दिल्ली, 2016, पृ. 122।
- सेन, अमर्त्य, डेवलपमेंट एज , ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली, 1999, पेज नं. 118।
- शर्मा, सुरेश, भारतीय शिक्षा प्रणाली में सुधार की दिशा, भारतीय प्रकाशन, नई दिल्ली, 2018, पृ. 45–47।
- सिंह, अनिल कुमार, भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य का तुलनात्मक अध्ययन, यूनिवर्सल बुक हाउस, लखनऊ, 2020, पृ. 88।
- यूनिसेफ, द स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स चिल्ड्रेन रिपोर्ट, न्यूयॉर्क, 2022, पृ. 135।
- वर्मा, रेखा, ग्रामीण भारत में शिक्षा और स्वास्थ्य चुनौतियाँ, अरुण प्रकाशन, इलाहाबाद, 2019, पृ. 82।
- डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट 2023: बिल्डिंग रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स, जिनेवा, 2023, पृ. 64।